

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

लं. 45]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 1980/फाल्गुन 22, 1901

No. 45]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 1980/PHALGUNA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न ही भासी हैं जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त संबंधीय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बजट भनुवाग

बजट 1980-81

वित्त मंत्री का भाषण

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1980

पढ़ सं. विंमं. (शोई) मू० शो० सं० 15(1)-बी (शो०)/80—
महोदय

में, वर्ष 1980-81 का अन्तरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए उपरिक्त
मुद्रा है।

2. भारत की अमता से क्रमाग्री पार्टी को जो विशाल जनादेश मिला
है वह स्तृप्त: सामाजिक और आर्थिक विकास के उन अद्वितीय से कार्यक्रमों
को फिर से नए उत्साह के साथ प्राप्त बढ़ाने का जतावेश है जिन्हें हमने
हमने 1977 से पहले प्रारम्भ किया था, किन्तु जो जनता-लोकदल शासन
के तेतीस महीनों के दौरान छिन्न-भिन्न हो गए थे। 1977 में हमने जो
सुवृद्ध और सक्रम अर्थव्यवस्था छोड़ी थी उसे और प्राप्त बढ़ाने की बजाय
उन्होंने अपनी निषिक्यता और कुप्रबन्ध के दबावारा गतिशुद्ध कर दिया।
इस स्थिति को सुधारने एवं तेजी से आर्थिक विकास के लिए ग्रथक परिश्रम
करने, गरीबी हटाने और सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा
20-सूक्ष्मी कार्यक्रम पर अमल करने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध
हैं। किन्तु, तेजी सहीने के जनता-लोकदल शासन के बावजूद जो अर्थव्यवस्था

हमें विरासत में मिली है वह ऐसी है कि उसकी क्षति का जायजा लेने
और उसमें फिर से नई जान ढालने तथा उसे सही स्थिति में लाने के
उद्देश्य से एक सुसंगत मध्यमकालिक नीति तैयार करने के लिए हमें
कुछ और समय की ज़रूरत होगी। लेकिन इसका मतलब यह सही है कि
‘हम अल्पकालिक गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए तब तक कोई
प्रभावशाली कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि एक संगत मध्यमकालिक
नीति नहीं बन जाती। अपने भाषण में मैं आगे बढ़ कर संक्षेप में उन
बहुत से उपर्योगी की रूपरेखा बनाऊंगा जो हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था
को स्थायीत्व प्रदान करने और उसमें फिर से भरोसा दैदा करने के लिए
पिछले आठ सप्ताहों में किए हैं। जाहिर है कि गांधी जी और जवाहरलाल
नेहरू ने हमें जो अभीष्ट पथ बिखाया है उस पर अपने देश को आगे ले
जाने के लिए बहुत से अन्य उपाय करने की ज़रूरत है। इस समन्वित
कार्यक्रम की स्परेक्षा में श्रवण लोने के लिए मैं, सदृश से कुछ सप्ताह के
बाद 1980-81 का नियमित बजट प्रस्तुत किये जाने तक प्रतीक्षा करने का
अनुरोध करूँगा।

3. अन्तरिम बजट और भनुवानों की मार्गे जो सम्मानित मदस्यों के
लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं उनमें पहले से स्वीकृत व्यय को ही
प्राप्त जारी रखा गया है और कुछ थोड़े से अन्तरिम बजट किये गए हैं जो
भिन्नविभिन्न थे। वे पर्याप्त रूप से वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों
के द्वयोत्तम नहीं हैं क्योंकि हमने जब से शासन भार संभाला है, हमें इन्हें
तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। हम यह महसूस करते
हैं कि पिछली सरकार ने जो योजना तैयार की थी वह उन नीतियों और
कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो हमने अपने अनाव

बोरोना-नत्र में जामिल किए थे और जिनके आधार पर हमें विश्वाल जनदेश मिला है। इसलिए हमें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि योजना आयोग का पुनर्गठन नहीं हो जाता और वह 1980-81 की प्राप्तिकलाओं और योजना-परिवर्त्यों को अन्तिम रूप नहीं दे देता। जब यह ये लिंगों के निये जाएंगे तब मैं फिर एक व्यापक कार्यश्रम नेतृत्व गदन के सामने उपस्थित होऊँगा।

4. जालू वर्ष में आधिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। वर्ष 1979-80 में मकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1 से 2 प्रतिशत की गिरावट आंगन की संभावना है। कौवि उत्पादन में 6 प्रतिशत के आयोग कर्मी होने की आमंत्रण है और शैद्योर्गिक उत्पादन में प्रगति की दर पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ी-सी कम या उननी ही रही। विश्वाल, कोयला, इमान, सीमेंट और उच्चरक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन में बृद्धि की दर अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। चालू विनिय वर्ष में कीमतें अधिक 20 प्रतिशत बढ़ी हैं। आस्तौर पर आम उपभोग की चीजों, जैसे चीनी, गृह, खाड़मारी, आम, प्याज तथा खाद्य नेतृत्वों की कीमतों में बहुत तेजी में बृद्धि हुई है। कीमतों पर यह दबाव जिनना देश में पूर्ति संबंधी कठिनाइयों के कारण है उननी ही बड़त के भारी घाटे के कारण भी है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी आयात की जाने वाली बस्तुओं की कीमतों में बृद्धि के कारण और देश में कम उत्पादन होने की वजह से इस्पात और सीमेंट जैसी बस्तुओं का अधिक आयात किये जाने के कारण व्यापारिक घाटा (हैप) पहले की अपेक्षा और उदादा बढ़ जाएगा। दूसरी ओर, स्पष्ट नीति न होने के कारण भी नियन्ति में पर्याप्त बृद्धि नहीं हुई है।

5. वर्ष 1979-80 के दौरान आधिक स्थिति में जो गिरावट आई है उसके लिए पिछले खरीफ के मौसम में पड़े सूखे को बहाना बनाना आसान होगा। यह मच है कि जालू मौसम में देश के बहुत बड़े भाग में भैंकर, सूखा पड़ा। लेकिन उसके बारे में हमारा विचार यह है कि हमारी पार्टी द्वारा सातवें दशक के आखिरी वर्षों में जो नई हृषि नीति शुरू की गई थी उस पर अमल कर के भौमिके उत्तर-दबाव के अभार को कम किया जा सकता था। यह विज्ञानी का उत्पादन अधिक होता और थीज, उच्चरक, डीजल आदि की पूर्ति की व्यवस्था अधिक प्रभावशाली होती तो पिछले खरीफ के भौमिके उत्पादन में जिस तरह की कीमि आई थी उसके कुप्रभाव से अर्थव्यवस्था को काफी हड़ तक बचाया जा सकता था। यदि कोई मरकार, पिछली जनता मरकार की तरह, 1977-78 और 1978-79 में भिली अच्छी सफलता के लिए श्रेय लेती है तो उसमें यही प्रकट होता है कि वह केवल अच्छे भौमिके पर ही निश्चर रहती है और उसके पाम कोई फलदायक नीति नहीं है। और जब सूखे के रूप में उस मरकार की पहली परीक्षा हुई तो उग्री नीति का दिवालियापाल मासमें आ गया और वह आम जनता को उबाजने में भी उच्च अमलक रही। उस समय जिस व्यवस्था ने उनका और देश की गरीब जनता का उद्धार किया, वह थी खरीद और सार्वजनिक वितरण की प्रणाली जो हमारी पार्टी ने बनाई थी और जिसके अन्तर्गत हमने आनज का विश्वाल भंडार उनके लिए छोड़ा था। हमें पिछली सरकार के प्रति अवश्य आमारों होना चाहिए क्योंकि उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह नष्ट-घस्त न करके कुछ रुपा की है।

6. हम समय आधारभूत धोनों में जो संकट की स्थिति व्याप्त है उससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले सीन वर्षों में अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध किनना खगब रहा है। हमारी पार्टी की मरकार ने पहले जो नियन्त्रित लिये थे उनके फलस्वरूप यथापि विद्युत उत्पादन की क्षमता में हड़ वर्ष भारी बहानी होती रही है तथापि अटिया प्रबन्ध, कानून और अवश्यक की समस्याओं और विगड़ हुए श्रीखंडिक सम्बन्धों के कारण हमें प्रतिरिक्षण क्षमता से उत्पादन नहीं बढ़ सका। यदि मरकार आवश्यक संकल्प और कल्पना-शक्ति का परिचय देती तो ये सब कठिनाइयां हड़ की जा सकती थीं। पिछले चार सालों में कोयले का उत्पादन बस्तुतः गतिरुद्ध हो गया। दूसरी ओर रेलवे के यातायात की मात्रा भी लगातार

घटती रही है। हमें यह अशोमन दृष्टि देखना पड़ रहा है कि विद्युत प्राधिकारी आपनी कमियों के लिए जहा एक और रेलवे और कोयला प्राधिकारियों को दोष दे रहे हैं वहां दूसरी और रेलवे तथा कोयला प्राधिकारी आपनी स्पष्टकलनाओं के लिए विद्युत प्राधिकारियों को और आपने में एक दूसरे को दोष दे रहा है। यदि इस निगाशाशनक नियन्त्रित की तुलना उसमें पहले के वर्षों की सफलताओं से की जाए तो यह अपने आप समझ में आए जाएगा कि एक प्रभावोत्पादक नीति से किसी कुछ प्राप्त किया जा सकता है।

7. मैंने पिछले सीन वर्षों के घटनाचक्र का उल्लेख एम उद्देश्य से नहीं किया है कि मैं किसी को दोष दू या किसी पर लोछन लगाऊ, लेकिन इसमें मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहा है कि मैं आप सांगों को उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पूरी तरह अवगत करा दूँ जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारी वर्तमान समस्याओं को बेख्ता जाना चाहिए। जाहिर है कि यह समय परस्पर दोषारोपण करने का नहीं है। वास्तविक चुनौती तो यह है कि देश के सामने इस समय जो संभीर समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए एक सक्षम राजनीय मौलिक सैयार किया जाए। हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में हम सदन के सामीं वर्गों से सक्रिया महयोग प्राप्त करना चाहते हैं। मैं इस प्रबन्ध पर सदन को अवगत करना चाहता हूँ कि हम वर्तमान गंभीर आधिक संकट से किस प्रकार निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब से हमने कार्यभार संभाला है, तब से हम कोयला, विद्युत, पलन और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों के कार्य में सुधार करने के लिए सुधारमित्र रूप में प्रयत्नशील हैं। श्रीखंडिक आधारभूत तंत्रों में संबंधित अन्तिमउल्लिय समिति कुछ प्रलक्षणिक हल खोजने में सफल हुई है जिससे इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य में सुधार होगा। नापीय विनूत संसदों को कोयले की पूर्ति की व्यवस्था को सुचाल भना दिया गया है और हमसे अच्छे परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं। पन-विज्ञानी के उत्पादन में जो कमी हुई है उसे अधिक से अधिक मात्रा में पूरा करने के लिए तापीय संसदों की क्षमता के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। रेल भी अपने कार्य के पहले से अधिक तेजी में और अधिक कुशलता के साथ पूरा करने के लिए अपने को तैयार कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि हमने जो कदम उठाए हैं वे श्रीखंडिक उत्पादन की बृद्धि करने, उपलब्ध क्षमताओं का उपयोग करने और कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में अवश्य ही प्रभावोत्पादक सिद्ध होंगे।

8. आधारभूत क्षेत्रों के कार्य के अन्वावा, सरकार कीमतों पर पड़ने वाले दबाव के कारण भी बहुत निनित है। हमें उत्तराधिकार में अत्यन्त विस्फोटक स्फीनिकारी अर्थव्यवस्था मिली है। अट्टन-भी कठिनाइयों के बावजूद, अब बनस्पति-बेनों, किरोसीन और डीजल जैसी आवश्यक बस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए और उनके समृच्छित वितरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए जोरदार कोशिशें की जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिक प्रभावोत्पादक संचालन और जमाल्लोरी तथा काला-बाजारी की रोकथाम के लिए गुरुवर्यवर्यत प्रयत्नों के द्वारा हम कम मात्रा में मिलने वाली बस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले दबाव पर काढ़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी, सीमेंट, कागज जैसी उपभोक्ता बस्तुओं के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक मध्यम-कालिक नीति तैयार की जा रही है। जब गंगार में गर्वन कीमतों बढ़ रही हो सां अपने देश में कीमतों को एक उचित स्तर पर स्थिर करना निस्संदेह कोई आमान काम नहीं है। किंतु भी, मरकार आवश्यक बस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए एक अवश्यकता विद्युत उपयोग करने के लिए कुत्सकल्प है। राजकोपीय और सौदिक नीतियों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि उनमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक निवेशों पर कोई बुध्रभाव डाले बिना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिले।

9. हालांकि अपना कार्यभार संभालने के बाद हमें जो सीमित समय मिला है उसमें हमारा व्याप्त आवश्यकतावश अधिकार ताल्कालिक गंभीर

समर्पयात्रों पर लगा रहा है, फिर भी हम आपने अपेक्षा मासांजिक और अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और समर्पित नीति तैयार कर रखे हैं। चूंकि भारत की अधिकांश जनता गतों में जर्जर है, हमलिए हमारी अर्थव्यवस्था के सामाजिक और अधिकांश कायाप्रजट को योजनाओं में कृषि और सबदृ व्यापकलापों के विकास को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1977 में हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में हमने एक कृषि विकास बैंक की शीघ्रता न्यायपत्र करने का वचन दिया था जो एक शीर्ष संस्था के रूप में हमारे किसानों को कृषि गवंधों आवश्यकताओं को पूरा करना। मूस मदन को यह बताते हुए खुशी ही रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस नये प्रन्तायन राष्ट्रीय यामोण विकास बैंक के संबंध में विधान का मसीदा तैयार करने में महत्व रूप से जटा हुआ है। हमारी सरकार ने ही फरवरी 1977 में मंगलोरी थोक के बैंकों के लिए यह तय किया था तिने अपने कुल प्रधिमों का कम से कम 33.3 प्रतिशत भाग छूपि, यामोधारा और लक्ष्य उद्योग थोकों की है। उम्मीद है कि ग्रन के दिनों में भैन गरकारों थोक के बैंकों के व्यवस्था (नेपरमेन) के साथ मिल कर यह यामोधारों की भी कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों को जटा तक सफलता मिली है और यह भी जर्जर की थी कि 20 सूखी व्यापक रूप से लक्ष्यन्वयन में तजी लाने के लिए बैंक का भूमिका अदा कर सकता है। मूस यह बताते हुए खुशी ही रही है कि सरकारी थोक के बैंकों ने अपार्श पांच वर्षों में अपने कुल प्रधिमों में साथ-सिकार-प्राप्त थोकों के हिस्से का 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के वायिष्य को स्वीकार कर लिया है। इससे ग्रामीण भारत के उत्पादक आधार की गुदूद करने में लक्ष्य अधिक गहराया रिहर्स है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपार्श संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे और सीमान्तिक किसानों तथा भूमिहीन भ्रमिकों वी आवश्यकताओं को प्राप्तिकता दी जाएगी।

1979-80 के संरोक्षित अनुमान

10. अब मैं संक्षेप में वर्ष 1979-80 के संरोक्षित अनुमानों की ओर आता हूँ।

11. वर्ष 1979-80 के बजट अनुमानों में 1382 करोड़ रुपए का बाटा विद्युता रखा था। पिछली सरकार द्वारा लिए गए कलिक्षण निर्णयों के कारण और बजट के बाबकी कुछ घटनाओं की वजह से चालू वर्ष में केंद्र की बजट संबंधी स्थिति पर बहुत बुरा प्रभार पड़ा है। जैसा कि अम्मानिन मध्यस्थियों को मालय है, हमें 1300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्व भाग समझ के पिछों लक्ष में प्रस्तुत करनी पड़ी थी। हमलिए मैं अतिरिक्त व्यय की विभिन्न महीनों पर विस्तार में जर्जर काफ़े क्रमों का लगातार नहीं देना चाहूँगा। मैं यहां केवल उन थोड़ी सी महीनों के बारे में ही बताऊंगा जिनमें भासतीर से बृद्धि होई है।

12. चालू वर्ष में खाच संबंधी अधिक सहायता पर 600 करोड़ रुपए दर्ज़ी 550 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों में 40 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होते; यह बृद्धि सूच्य रूप से रहे हैं और बाज़ की कीमतों में बढ़ाती होने के कारण हुई है।

13. ग्रामान्तर उर्वरकों की लागत में बृद्धि, उर्वरक आयात की मात्रा में बृद्धि और उनको उठाने-धरने की लागत में बृद्धि हो जाने के कारण, अतिरिक्त उर्वरकों पर अधिक सहायता की राशि, 144 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की अपेक्षा 176 करोड़ रुपए अधिक होती है। हीनी प्रकार उर्वरकों की लागत में बृद्धि हो जाने के कारण, देशी उर्वरकों पर दी जाने वाली अधिक सहायता 30.1 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 19 करोड़ रुपए अधिक होती है।

14. चौमी निर्यातों पर होने वाली हानि सहित निर्यात संबंधी अधिक सहायता के लिए बजट अनुमानों में 332 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी लेकिन अब व्यस्थे 31 करोड़ रुपए की बृद्धि हो जाएगी।

15. चालू वर्ष में रेखा व्यय 3273 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है जिसकी बजट में 3050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

16. गज्जों की दी जाने वाली आयोजना-भिन्न सहायता की राशि वे इस वर्ष 120 करोड़ रुपए की बृद्धि करनी पड़े। जिसमें कि राज्य दैर्य विवादों और सूखे के लिए राहने वाली के खर्चों को पूरा कर गए पर्यवेक्षकों के संप्रभु के बजाने गत्य सरकारों के लिए जाने वाले उदाहरण का राशि भी 400 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 225 करोड़ रुपए अधिक होती है।

17. बजट के बाद जो और घटाएं घटाएं उनमें एक और बांगना देश की खाचाप्रधार की पूर्ति जिस पर 29 करोड़ रुपए और सूखे के लिए राहने वाली के आम भूमियों के संबंध में राज्य सरकारों का 30 करोड़ रुपए की 'विवादों' भ्रातावार। इसके अतावा, भूमिका वित्त के कार्यों और पैशान सम्बन्धी लाभों को उदाहरण बताने के लिए मार्च 1979 में जो निर्यात लिया गया उसके कारण दूसरे भी रक्षा, रेलवे और डाक-नाम नहीं बढ़ने से भरनारों विवादों के बजाने से बृद्धि हो गई।

18. अब उन अत्याजनन-अनुमान का सम्बन्ध है, यह खोद का विषय है कि बहुत में अद्वितीय आयोजनागत विवादों के कार्यान्वयन की प्रशंसित मतान्वयन नहीं रही है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन गणि में अनुमान 332 करोड़ रुपए की कर्मी होती है। किन्तु बास के बद्रों अनुमान के लिए कांगड़ गणि में चालू वर्ष के द्वितीय 300 करोड़ रुपए की बृद्धि हुई है, यद्योंके प्रारम्भ में इस कार्यक्रम के लिए कंगड़ 60 करोड़ रुपए की छोटी सी व्यवस्था की गई थी और इसलिए केंद्रीय आयोजना के व्यवस्था में 32 करोड़ रुपए की निवाल कर्मी होती है।

19. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता में आमू वर्ष के द्वितीय 194 करोड़ रुपए की बृद्धि करनी पड़े। इस बृद्धि में 125 करोड़ रुपए सूखा-प्रभावित राज्यों को आंग्रेज आयोजना सहायता के रूप में देने के लिए है।

20. जहां तक प्राप्तियों का गम्भीर व्यवस्था को असंतोषजनक प्रभावित और अधिक बृद्धि की दर में गामाच्य रूप में कर्मी आ जाने के कारण, चालू वर्ष के द्वितीय सरकार की नियम कर से प्राप्त होने वाले राज्यम् में 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की संभावन है जबकि बजट में इस दर से 1630 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाले ग्रासव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसका बहुत कुछ कारण यह है कि पिछली सरकार ने कोपने पर गे उत्पाद शुल्क हटा दिया था और पेंट्रालियम उत्पादों के शुल्क की दर में कर्मी कर दी थी। अनुमान है कि चालू वर्ष में उत्पाद शुल्क में 6008 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 183 करोड़ रुपए की कर्मी रहेगी। किन्तु आयकर सम्बद्ध और सीमा-शुल्कों की प्राप्तियों में 3636 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 498 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने की उम्मीद है। अनुमान है कि निवाल कर-ग्रामस्व में केन्द्र का हिस्सा 8020 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 199 करोड़ रुपए अधिक होगा।

21. आवारभूत बांधों के लगान बैठ जाने और अधिक तत्वों के प्रतिकूल हो जाने के कारण ग्रामकारी सेत्रों के विभिन्न उपकरणों के कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्यामासवरूप न केवल उनकी लाभान्वय धमता है कम हो गई है बल्कि सरकार की अपूर्ण कामोदी और व्याज की अद्यायी की बेंदारी को पूरा करने के लिए भी उनकी धमता को घटका पहुँचा है। चालू वर्ष के द्वितीय इस खाते में लगान 260 करोड़ रुपए की कर्मी रहने की आशंका है।

22. कुछ विवेणी सहायता-प्राप्ति परियोजनाओं में भूगतान की गति धीमी होने के कारण और कुद्रेमुख परियोजना के लिए ईरानी प्राधिकारियों

से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में देरी हो जाने के कारण, चालू वर्ष के दौरान निवाल विवेशी सहायता में 219 करोड़ रुपए की कमी रहने की संभावना है।

23. आयातित कूछ और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण भी तेल उत्पादों के मध्यम में सरकार को प्राप्त होने वाली और उसके पास जमा होने वाली राशियाँ में 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमी हो गई है।

24. किन्तु कर-भिन्न प्राप्तियाँ में जो कमी हुई है वह 1850 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 111 करोड़ रुपए के अधिक बाजार ऋणों के द्वारा और 650 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 925 करोड़ रुपए के अत्यधिक बचत संग्रह के द्वारा आर्थिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई है।

25. उपर्युक्त और कुछ दूसरी घटबढ़ को हिसाब में लेने पर, अनुमान है कि इस वर्ष बजट में भागधन 2700 करोड़ रुपए का बाटा रहेगा।

1980-81 का बजट अनुमान

26. अब मैं 1980-81 के अन्तर्गत बजट प्रस्तावों के बारे में भी कुछ शब्द रखना चाहूँगा।

27. वर्ष 1980-81 के बजट में, जो कि इस समय 'लेखानुवान' के प्रयोजन से पेश किया जा रहा है, केन्द्रीय आयोजना के लिए 4500 करोड़ रुपए की समर्थन राशि रखी गई है। सरकार 'काम के बदले भगाज' की वर्तमान योजना को कुछ नवा रूप देने के लिए यिचार कर रही है ताकि उसे रोजगार बढ़ाने का एक अधिक समर्क साधन बनाया जा सके। इसलिए, बजट में फिलहाल मौजूदा योजना के लिए केवल 70 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की जा रही है। इसे भी हिसाब में शामिल करने के बावजूद, केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट में 4570 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा जबकि वर्ष 1979-80 के बजट अनुमानों में इसके सिंग 4411 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी।

28. केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट से बाहर के साधन भग वर्ष अनुमानतः 2003 करोड़ रुपए के होने तक चालू वर्ष के बजट में यह राशि 1604 करोड़ रुपए की थी। इस प्रकार भगले वर्ष के लिए कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय, चालू वर्ष के बजट में 6015 करोड़ रुपए की तुलना में 6573 करोड़ रुपए रखा रहा है।

29. याज्ञों और संघ राज्य धर्मों के लिए केन्द्रीय सहायता, जिसमें ग्रामीण विद्युती कारण निगम की योजनाएं और 'आय समायोजित कुल जनसंख्या' सूत के प्रन्तर्भ की जाने वाली सहायता शामिल है, वर्ष 1979-80 के बजट में रखे गए 2697 करोड़ रुपए की तुलना में 2823 करोड़ रुपए की होगी। योजना आयोग ने राज्ञों और संघ राज्य धर्मों की सरकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके, उनकी वर्ष 1980-81 की आर्थिक आयोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित कर दिए हैं। इन परिव्ययों में उचित वृद्धियाँ की गई हैं कि जिससे कि विकास की गति को बनाए रखा जा सके। राज्ञों ने योजना आयोग को आशावान दिया है कि वे साधनों की निर्धारित स्तर पर उपलब्ध रखेंगे और इन परिव्ययों की वित्त-व्यवस्था करने के लिए भ्रतिरक्त साधन जुटाने के बारे में उन्होंने जो बचत दिए हैं उनका पालन करेंगे।

30. वर्ष 1980-81 में खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है यह उत्तरी ही राशि है जितनी कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में रखी गई है। जब तक कि देश में उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक आयात की मात्रा का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल जाता, तब तक आयातित और स्वेच्छीय उत्पादों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि भगले वर्ष 600 करोड़ रुपए रखी गई है।

31. इम समय 3300 करोड़ रुपए के रक्षा व्यय का अनुमान लगाया गया है जबकि चालू वर्ष में यह राशि 3273 करोड़ रुपए थी।

32. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय के लिए व्यवस्थाएं इत्यन्त मिन्ड्यगत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है।

33. करों की वर्तमान दरों पर कर-राजस्व में केन्द्र का हिस्सा भगले वर्ष अनुमानतः 8725 करोड़ रुपए का होगा जबकि चालू वर्ष के मंशोधित अनुमानों में इसकी राशि 8219 करोड़ रुपए रखी गई है।

34. भाजार ऋणों से प्राप्तियाँ, चालू वर्ष के 1961 करोड़ रुपए के मुकाबले, अनुमानतः 2500 करोड़ रुपए की होंगी। अल्प दरों से, चालू वर्ष के 925 करोड़ रुपए की तुलना में, अगले वर्ष 1000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वापसी अद्याधीनी की रकमों को घटा कर, निवल विदेशी भवायता के रूप में 1196 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 918 करोड़ रुपए है।

35. अनुमान है कि वर्ष 1980-81 में केन्द्रीय सरकार की कुल प्राप्तियाँ 18980 करोड़ रुपए की होंगी। अगले वर्ष कुल व्यय 20215 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रवाह करातार की मीठूदा दरों के अनुसार बजट में कुल मिला कर 1235 करोड़ रुपए का बाटा रहेगा।

36. आज मैं एक वित्त विवेयक पेश करना चाहता हूँ जिसके द्वारा मीठूदा दरों को वित्तीय वर्ष 1980-81 में जाने रखने की अनुमति मांगी जाएगी। लेकिन मेरे पास प्रायकर अधिनियम में संशोधन के लिए तीन प्रस्ताव हैं जो विवादास्वर नहीं हैं। अब मैं संझें में इन प्रस्तावों की व्याख्या करूँगा।

37. कुछ राज्य सरकारों ने प्रतिसूचित जासियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक हितों के संवर्द्धन के लिए कानूनी नियम स्थापित किए हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के हितों के संवर्द्धन के लिए स्थापित, उन सभी कानूनी नियमों, नियायों, संस्कारों या संगमों की प्राप्त की, जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हों, प्रायकर से मुक्त कर दिया जाए।

38. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, लहान के लोगों को, उस जिने में या भारत से बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त या प्रोत्स्थूत आय के संधंध में 1979-80 के कर-निधारण वर्ष तक जिसमें यह वर्ष गायिल है, प्रायकर की अवायवी से छठ दी गई थी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह छठ आगे भी वर्ष तक और की जाती रहे।

39. वर्तमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, साहित्यिक और कलात्मक कार्य व्यवस्था उपलब्धि के निए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिसूचित पुरस्कारों (प्रवार्ड) पर कोई आय कर नहीं लगता। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रकार की कर-रियायत गरीब, कमजूदा और भीमार लोगों के दुःखरात्र की कम करने के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिसूचित पुरस्कारों पर भी सागू की जाए। सम्मानित सदस्यों को यह जानकार प्रसंगता होगी कि इस व्यवस्था के कर दिए जाने से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मदर टेरेना की दिए गए नोबल पुरस्कार की करायेता के बारे में जो संवेद उठ रहे हैं वे शान्त हो जाएंगे।

40. सीमा गुल्क और केन्द्रीय उत्पाद गुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। किन्तु वित्त विवेयक में 1980-81 के लिए मीठूदा दरों पर सहायक सामान्युकों और विशेष उत्पाद गुल्कों को आरी रखने की व्यवस्था की गई है।

41. महोपय, कुछ सप्ताह के द्वारा 1980-81 का नियमित बजट दीयार परने के सम्बन्ध में थी, सदन से रचनात्मक सुसाव प्राप्त करने की अधिकारा करता है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economics Affairs)

BUDGET DIVISION

BUDGET 1980-81

SPEECH OF MINISTER OF FINANCE

New Delhi, the 11th March, 1980

Sir,

I rise to present the Interim Budget for the year 1980-81.

2. The massive mandate that our Party has received from the people of India is clearly a mandate to pursue with renewed vigour various programmes for social and economic development initiated by us before 1977 but which were disrupted during the thirty-three months of the Janata-Lok Dal rule. Instead of building further the strong and resilient economy which we had left behind in 1977, they have allowed it to drift, through inaction and mismanagement, into stagnation. Our commitment to repair this damage, to work tirelessly for rapid economic development, for removal of poverty and social inequalities and for the implementation of the 20-point programme is firm and irrevocable. However, the state of the economy that we have inherited from the Janata-Lok Dal rule of thirty-three months is such that we shall need some more time to assess the damage suffered by the economy and to evolve a coherent medium-term strategy for revival and restoration of its health. This, of course, does not mean that we will not take effective steps to deal with the pressing short-term problems until such a consistent medium-term strategy has been evolved. Later in my speech, I shall outline briefly the various steps which our Government has taken in the last eight weeks to restore a measure of confidence and stability to the economy. Clearly, there is need to adopt many other measures to get our country moving again along the cherished path set out by Gandhiji and Jawahar Lal Nehru. For the outline of such an integrated approach, I plead with the House to wait until I come forward with the regular Budget for 1980-81 in a few weeks later.

3. The Interim Budget and the Demands for Grants being made available to Honourable Members reflect by and large the continuation of on going expenditure sanctioned earlier and certain minimum unavoidable changes. They do not reflect adequately the present Government's policies and programmes because since we took office we have not had enough time to formulate these. We feel that the Plan framed by the previous Government is inadequate to fulfil the policies and programmes set out by us in our election manifesto and on the basis of which we have received a massive mandate. We have therefore to wait till the priorities and plan outlays for 1980-81 are finalised by the Planning Commission to be appointed. I shall come to the House again with a comprehensive programme when these decisions have been taken.

4. In the current year the economic situation has deteriorated greatly. The year 1979-80 is likely to record a decline

of 1 to 2 per cent in Gross National Product. Agricultural production is expected to show a decline of something like 6 per cent and industrial production will be stagnant if not marginally lower than last year. The growth in key sectors like power, coal, steel, cement and fertilizers will be wholly inadequate to meet the needs of a growing economy. Prices have risen by about 20 per cent in the course of the current financial year. In particular, prices of some of the items of common consumption such as sugar, gur, khandsari, potatoes, onions and edible oils have recorded very sharp increases. This pressure on prices is as much due to domestic supply constraints as to a large budget deficit. The trade gap is going to be vastly larger because of the increase in prices of imports like petroleum and petroleum products and because of the larger imports of commodities like steel and cement due to poor domestic production. On the other hand, exports have not grown adequately because of lack of a clear policy.

5. It will be easy to make the drought in the last kharif season an excuse for the deterioration in the economic situation in 1979-80. It is true that the drought was serious in large parts of the country in the current season but one would have thought that the new agricultural strategy initiated by our Party in the late 1960s could have enabled the Government to minimise the impact of the fluctuations in weather conditions. Had power production been higher and had arrangements for supplying seeds, fertilizers, diescl etc., been more effective, it would have been possible to insulate the economy to much greater extent against the kind of decline in production that has occurred in the last kharif season. A Government which takes credit, as the previous Janata Government did, for the good performance in 1977-78 and 1978-79 merely underscores its dependence on good weather and its lack of effective policy instruments. And when the first test came in the form of a drought, the Government showed the bankruptcy of its policy and failed miserably to protect the common people. What has come to their rescue as well as to that of the poor people of the country has been the procurement and public distribution system that our Party had built up earlier and the large stocks of foodgrains that it had left to them. We must be thankful to the previous Government for the small mercy they had shown in not dismantling the public distribution system completely.

6. The mismanagement of the economy in the past three years can be seen most vividly in the crisis situation which prevails in the infrastructure sectors. Although large additions to power generating capacity have occurred year after year as a result of the decisions taken by our Party's Government earlier, the ability to generate power from this additional capacity has been very poor. Poor management, law and order problems, disturbed industrial relations—all of which could have been set right had the Government shown the necessary determination and imagination—have come in the way of higher production. Coal production has remained virtually stagnant for the last four years. Railways on the other hand have been carrying a continuously declining volume of traffic. We have had to witness the unedifying spectacle of the Power authorities blaming the Railways and Coal authorities for their deficiencies and these in turn blaming the Power authorities and each the other for their failures. This dismal record has only to be compared with the performance in the earlier years to realise what an effective policy can achieve.

7. I have referred to the developments in the past three years, not with a view to apportion blame or trade accusations but merely to highlight the historical setting in which

our current problems have to be viewed. This is clearly not the time for indulging in mutual recriminations. The real challenge is to evolve a viable national consensus for solving the formidable problems now facing the country. In this vital national task, we seek the active co-operation of all sections of the House. I would like to take this opportunity to share with the House the manner in which we are tackling the present grave economic crisis. Since we assumed office, systematic efforts are being made to improve the functioning of vital infrastructure sectors such as coal, power, ports and Railways. A Cabinet Committee on Industrial Infrastructure has been able to identify some short-term solutions designed to improve the working of these vital sectors. Arrangements for supply of coal to thermal power plants have been streamlined and these are beginning to show positive results. Efforts are being made to improve the capacity utilisation of thermal plants so as to neutralise to the maximum extent the shortfall in the generation of hydro power. The Railways are gearing themselves to carrying out their tasks with greater speed and efficiency. I am confident that the measures which we have taken will have a favourable impact on the growth of industrial production, on the utilisation of available capacities and in moderating pressure on prices.

8. Apart from the functioning of infrastructure sectors, Government has been greatly worried about the pressure on prices. We have inherited a highly explosive inflationary economy. Despite several handicaps, vigorous efforts are now being made to augment supplies of essential commodities like vegetable oils, kerosene and diesel and to ensure their equitable distribution. Through a more effective functioning of public distribution system and systematic efforts to curb hoarding and blackmarketing, we are trying to contain the pressure on prices of commodities which are in short supply. A medium term strategy being evolved to encourage higher production of consumer goods like sugar, cement, paper, etc. In the background of world wide inflationary pressures, our task of stabilising domestic prices at a reasonable level is no doubt far from easy. However, Government is determined to use all available instruments to moderate pressure on prices of essential commodities. Fiscal and monetary policies will be so designed as to assist in control of inflation without affecting essential investments in key sectors of the economy.

9. While in the limited time we have had at our disposal since we assumed office our attention has of necessity been focussed largely on pressing immediate problems, we are beginning to evolve a comprehensive integrated strategy for achieving our cherished social and economic objectives. Since the bulk of Indian population lives in rural areas, development of agriculture and allied activities must receive high priority in our plans for social and economic transformation of our economy. It was in pursuit of this objective that our Party's election manifesto in 1977 had committed us to the early establishment of an Agricultural Development Bank as an apex institution for meeting the credit needs of our farmers. I am glad to report to the House that the Reserve Bank of India is now actively engaged in drafting the legislation of the proposed National Bank for Rural Development. It was again our Government which in February 1977 had set for the public sector banks a minimum target of 33.3 per cent of total advances going to the hitherto neglected sectors of agriculture, village and small industries. Earlier this month, I have reviewed with the Chairmen of public sector banks the performance of the banking system in achieving this target as well as the role that the banking system can play in accelerating the implementation of the

20-point programme. I am glad to report that public sector banks have agreed to accept the obligation of raising the share of priority sectors in their total lending to 40 per cent in the next five years. This will greatly help in strengthening the productive base of rural India. In meeting the credit needs of rural areas, priority attention will be given to requirements of small and marginal farmers and landless labourers.

Revised estimates for 1979-80

10. I now turn to a brief explanation of the Revised estimates for the year 1979-80.

11. A deficit of Rs. 1382 crores was estimated in the Budget for 1979-80. Certain decisions taken by the previous Government and other post-budget developments have severely affected the budgetary position of the Centre in the current year. As the Honourable Members are aware, supplementary demands involving additional expenditure of Rs. 1300 crores had to be presented in the last session of Parliament. I will, therefore not like to take the time of the House by dwelling at length on the various items of additional expenditure. I shall confine myself now only to certain major areas of increases.

12. Expenditure on food subsidy in the current year will be Rs. 600 crores i.e. Rs. 40 crores more than the Budget estimate of Rs. 560 crores—mainly due to increase in the procurement prices of wheat and paddy.

13. Owing to increase in the cost of imported fertilizers, increased volume of fertilizer imports and higher handling costs, the subsidy on imported fertilizers will be Rs. 176 crores more than the Budget estimate of Rs. 144 crores. Similarly, due to higher cost of production, the subsidy on indigenous fertilizers will be Rs. 19 crores more than the Budget estimate of Rs. 304 crores.

14. The provision for export subsidies including loss on sugar exports will be Rs. 31 crores more than the Budget estimate of Rs. 332 crores.

15. Defence expenditure in the current year is estimated at Rs. 3273 crores against the Budget provision of Rs. 3050 crores.

16. Non-Plan assistance to State Governments had to be stepped up in the current year by Rs. 120 crores to enable them to meet the expenditure on relief for natural calamities and drought. Loans to State Governments against net collections of small savings will also be Rs. 225 crores more than the Budget estimate of Rs. 400 crores.

17. Other post budget developments include supply of foodgrains to Bangladesh involving an expenditure of Rs. 29 crores, and 'on account' payment of Rs. 30 crores to State Governments in connection with the General Elections to Lok Sabha. Besides, the decisions taken in March 1979 for liberalisation of dearness allowance formula and pensionary benefits have also added to the expenditure of various Government departments, including Defence, Railways and Posts and Telegraphs.

18. So far as Plan expenditure is concerned, it is a matter of regret that the implementation of many of the Central Plan schemes has not been satisfactory. Consequently, the budgetary support for Central Plan is estimated to be less by as much as Rs. 332 crores. However, the provision for 'food for work' programme has been stepped up by Rs. 300 crores during the course of the year as a small provision of only Rs. 50 crores had been made for this programme initially, and consequently, the net shortfall in the Central Plan expenditure will be Rs. 32 crores.

19. The Central assistance for States' and Union Territories' Plans had to be stepped up by Rs. 194 crores during the current year. Of this increase, Rs. 125 crores is by way of advance Plan assistance to States affected by drought.

20. Coming to receipts, owing to poor performance of the economy and the general decline in economic growth, the revenues of Central Government from corporation tax in the current year are expected to register a sharp decline of Rs. 150 crores compared to the Budget estimate of Rs. 1530 crores. The revenues from Union excise duties have also been adversely affected largely by the decision of the previous Government to withdraw excise duty on coal and reduce the duties on petroleum products. The excise duties are estimated to register a shortfall of Rs. 183 crores in the current year compared to the Budget estimate of Rs. 6008 crores. However, collections of income-tax and receipts from customs duties are expected to yield Rs. 498 crores more than the Budget estimate of Rs. 3636 crores. Centre's share of net tax revenue is now estimated to be Rs. 199 crores more than the Budget estimate of Rs. 8020 crores.

21. The near collapse of infrastructure and the adverse economic factors have severely affected the working of various public sector undertakings. Consequently, not only their profitability has been eroded, but their capacity to meet their repayment and interest obligations to Government has also been undermined. A shortfall of nearly Rs. 260 crores on this account is anticipated in the current year.

22. The slow pace of disbursements in certain externally aided projects and delay in getting reimbursement for the Kudremukh Project from the Iranian authorities are likely to result in a shortfall of Rs. 219 crores in net external aid during the current year.

23. The increase in prices of imported crude and petroleum products has also led to erosion of the receipts and deposits with Government relating to oil products of over Rs. 300 crores.

24. These deteriorations in non-tax receipts have, however, been partially offset by a larger market borrowing of Rs. 111 crores over the Budget estimate of Rs. 1850 crores and estimated higher small savings collections of Rs. 925 crores as against the Budget estimate of Rs. 650 crores.

25. Taking these and other variations into account, the budgetary deficit in the current year is estimated to be about Rs. 2700 crores.

Budget Estimates for 1980-81

26. I shall now say a few words about the interim Budget for 1980-81.

27. In the Budget for 1980-81 which is now being presented for purposes of 'vote on account', budgetary support for Central Plan is placed at Rs. 4500 crores. Government is considering revamping of the present scheme of 'food for work' to make it a more potent instrument of employment generation. For the present, therefore, a provision of only Rs. 70 crores is being made in the Budget for the existing scheme. Taking this also into account, budgetary support for Central Plan will be Rs. 4570 crores against the Budget estimate of Rs. 4411 crores for the year 1979-80.

28. Extra budgetary resources for the Central Plan are estimated at Rs. 2003 crores next year as against Rs. 1604 crores in the current year's Budget. The total Central Plan outlay for next year is thus placed at Rs. 6573 crores as compared to Rs. 6015 crores in the current year's Budget.

29. Central assistance for States' and Union Territories' Plans, including the schemes of the Rural Electrification Corporation and assistance under 'Income Adjusted Total Population' formula, is placed at Rs. 2823 crores as against Rs. 2697 crores in the Budget for 1979-80. The Planning Commission has in consultation with the representatives of State Governments and Union Territories settled the outlays for their Annual Plans for the year 1980-81. A reasonable step-up in the outlays has been provided so that the tempo of development may be maintained. The States have assured the Planning Commission that they will keep the resources at the assessed level and adhere to the commitments made by them to mobilise additional resources to finance these outlays.

30. Provision for food subsidy in 1980-81 is Rs. 600 crores, i.e. at the same level as in the Revised estimate for the current year. Pending a clearer picture of the volume of imports needed to supplement domestic production, subsidy on imported and indigenous fertilizers next year is placed at Rs. 600 crores.

31. Defence expenditure is estimated at Rs. 3300 crores at this stage against Rs. 3273 crores in the current year.

32. Provisions for other non-Plan expenditure have been made keeping in view the need for utmost economy.

33. The Centre's share of tax revenues at existing rates of taxation is estimated at Rs. 8725 crores next year, as against Rs. 8219 crores in the Revised estimates for the current year.

34. Receipts from market borrowings are estimated at Rs. 2500 crores against Rs. 1961 crores in the current year. Small savings collections are estimated to fetch Rs. 1000 crores as against Rs. 925 crores in the current year. External assistance, net of repayments, is estimated at Rs. 1196 crores as against Rs. 918 crores in the Revised estimate of the current year.

35. The total receipts of the Central Government in the year 1980-81 are estimated at Rs. 18980 crores. The total expenditure in the next year will be Rs. 20215 crores. Overall budgetary gap at the existing rates of taxation will thus be Rs. 1235 crores.

36. I propose to introduce today a Finance Bill which seeks to continue the existing rates of income-tax for the financial year 1980-81. However, I have also three proposals of a non-controversial nature for the amendment of the Income-tax Act. I shall now briefly explain these proposals.

37. Some State Governments have set up statutory corporations for the promotion of socio-economic interests of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I propose to exempt from income-tax the income of all statutory corporations or bodies, associations or institutions wholly financed by the Central or a State Government, established for promoting the interests of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

38. As the Hon'ble Members are aware, residents of Ladakh were exempted from payment of income-tax upto and including the assessment year 1979-80 in respect of income accruing or arising to them from any source in that district or outside India. I propose to continue the tax exemption for a further period of three years.

39. Under the existing provisions, awards for literary, scientific and artistic work or attainment, instituted by the Central Government or by any State Government or approved

by the Central Government, are exempt from income-tax. I propose to extend this tax concession to approved awards for outstanding work in alleviation of the distress of the poor, the weak and the ailing. Hon'ble Members will be glad to know that this provision will set at rest doubts about the taxability of the Nobel Prize awarded to Mother Teresa in recognition of her service to suffering humanity.

40. There is no change in the rates of customs and Central excise duties. However, provision has been made in the Finance Bill for the continuance the auxiliary duties of customs and special duties of excise at the existing rates for the year 1980-81.

41. Sir, I look forward to constructive suggestions from the House for framing the regular Budget for 1980-81, a few weeks later.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.